भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 400
05 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः किसान उत्पादक संगठन
400. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितने किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) हैं;
(ख) क्या सरकार ने एफपीओ पर कर लगाने के लिए कोई नीति तैयार की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एफपीओ के संवर्धन के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

<u>उत्तर</u>
<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क): भारत सरकार 10,000 नए एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) लागू कर रही है। दिनांक 31.10.2023 तक उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक 7476 एफपीओ पंजीकृत किये जा चुके हैं। पंजीकृत एफपीओ की राज्य-वार संख्या अनुबंध पर दी गई है।

(ख) एवं (ग): कंपनी अधिनियम के तहत एफपीओ के कराधान के लिए मौजूदा प्रावधान इस प्रकार हैं:
i. कंपनी अधिनियम के तहत: धारा 80पीए के तहत, उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत एफपीओ को 100 करोड़ रुपये तक आयकर से छूट मिलती है। कंपनियों के रूप में पंजीकृत एफपीओ को धारा 115जेबी (एमएटी प्रावधान) के प्रावधानों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करना होगा।
ii. सहकारी अधिनियम के तहत: सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत एफपीओ को धारा 115जेसी का लाभ मिलता है और उनकी कुल आय धारा 80पी के तहत उपलब्ध कटौती से कम हो जाती है। इस प्रकार सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत एफपीओ को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) या आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

(घ): चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 10,000 एफपीओ के गठन और प्रचार के लिए सीएसएस के तहत 955 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है।

*****

अनुबंध

पंजीकृत एफपीओ की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत एफपीओ की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	7
2	आंध्र प्रदेश	338
3	अरुणाचल प्रदेश	106
4	असम	289
5	बिहार	465
6	छत्तीसगढ़	158
7	दादरा नगर हवेली	--
8	गोवा	8
9	गुजरात	386
10	हरियाणा	146
11	हिमाचल प्रदेश	116
12	जम्मू और कश्मीर	199
13	झारखण्ड	268
14	कर्नाटक	270
15	केरल	120
16	लद्दाख	3
17	लक्षद्वीप	1
18	मध्य प्रदेश	561
19	महाराष्ट्र	516
20	मणिपुर	69
21	मेघालय	52
22	मिजोरम	48
23	नागालैंड	81
24	ओडिशा	405
25	पुदुचेरी	4
26	पंजाब	117
27	राजस्थान	470
28	सिक्किम	13
29	तमिलनाडु	388
30	तेलंगाना	263
31	त्रिपुरा	50
32	उत्तर प्रदेश	1137
33	उत्तराखंड	134
34	पश्चिम बंगाल	288
	कुल योग	**7476**

*****